

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-345/2015

काशीराम खाती

—अपीलार्थी

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), हनुमानगढ, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.02.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

- इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 21.07.1982 के द्वारा अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.08.1982 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 23.08.1982 से स्थाई की गई, जिसका उल्लेख अपीलार्थी के सेवा अभिलेख में अंकित है। अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया, जिसके लिए अपीलार्थी की सेवा उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 23.08.1982 से गिनी गई। अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ गलत रूप से दिनांक 08.10.2012 से दिया गया। उसके लिए अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग की दिनांक 06.09.1985 से गिनी गई। जबकि अपीलार्थी की सेवा दिनांक 23.08.1982 से गिनी चाहिए थी। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 23.08.1982 से सेवा की गणना करते हुए तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये और आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2012 अपास्त किया जाये।
- प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नियमित नियुक्ति स्क्रीनिंग के पश्चात ही नियमित मानी गई है। ऐसे में अपीलार्थी की स्क्रीनिंग की दिनांक 06.09.1985 से अपीलार्थी की नियमित सेवाएं उसी दिनांक से मानी जा सकती है। उसके पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी द्वारा तदर्थ रूप में दी गई थी, जिसे

चयनित वेतनमान और अन्य लाभ के लिए अपीलार्थी अपने सेवाकाल में नहीं जुड़वा सकता हैं।

3. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से अपनी प्रथम नियुक्ति का आदेश दिनांक 21.08.1982 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से दी गई थी। अपीलार्थी की सेवाएं नियमित किये जाने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसका उल्लेख अपीलार्थी ने अपनी अपील में किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के बाद नियमित माना है।
4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from

the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

5. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रीनिंग के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुडवा सकता है।
6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)